

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02

अंक - 291

जौनपुर, गुरुवार, 18 जुलाई 2024

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

बिभव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ हमले के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार के खिलाफ 50 गवाहों के साथ आरोप पत्र दायर किया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल की अदालत में 50 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई। बिभव कुमार न्यायिक हिरासत के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए, जिसे मजिस्ट्रेट ने 30 जुलाई तक बढ़ा दिया है। बिभव कुमार को 30 जुलाई को अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा, जब आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। आरोप पत्र में 50 गवाहों के बयान शामिल हैं। राज्यसभा में आप सांसद स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। उन्हें 27 मई, 7 जून और 12 जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। कुमार पर कई आरोप और आरोप हैं - गलत तरीके से रोकना, किसी महिला की गरिमा को अपमानित करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल, आपराधिक धमकी, एक महिला की विनम्रता का अपमान, गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास, सख्तों को नष्ट करना। और गलत जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

सिंधिया ने शीर्ष दूरसंचार प्रमुखों से मुलाकात की

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की हितधारक सलाहकार समिति (एसएसी) की बैठक में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने बड़ी टेलीकॉम सर्विस देने वाली कंपनियों के मालिकों से बात की। इस बैठक में भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल, रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी, एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल और वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मूंदडा से मुलाकात की। बैठक के दौरान उद्योग जगत के नेताओं ने मंत्री को देश में 5जी क्रियान्वयन की प्रगति, दूरसंचार कम्पनियों के समक्ष चुनौतियों तथा सेवा वितरण को बढ़ाने की संभावित रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। प्रदाताओं की सलाहकार समिति के साथ बहुत ही उपयोगी बैठक हुई। बैठक के बाद सिंधिया ने ट्वीट किया, भविष्य और विकास के अभिनव क्षेत्रों सहित क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। हम एक समावेशी और कनेक्टेड भारत बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने कसी कमर

लखनऊ, संवाददाता। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी



आदित्यनाथ ने बुधवार को उन 30 मंत्रियों के साथ बैठक की, जिन्हें चुनाव वाली सीटों पर प्रभारी बनाया गया है। बैठक में मंत्रियों को सभी सीटों जीतने का टास्क देते हुए

भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है - अखिलेश

लखनऊ, संवाददाता। समजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी में चल रहे घटनाक्रम पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में, उग्र में शासन-प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। बीते दिनों लखनऊ में हुई भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान से

कहा कि हर हाल में 10 सीटों को जीतना है। इसके लिए मंत्री सप्ताह में कम से कम दो दिन उसी क्षेत्र

में रात्रि प्रवास जरूर करें और चुनाव समाप्त होने तक वहां डूटे रहे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं से संवाद करने और उनकी समस्याओं का

अभी केजरीवाल को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की वैधता पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर दलीलें सुनने के लिए कोर्ट ने 29 जुलाई की तारीख तय की है। इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को अभी भी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत पर बहस भी पूरी कर ली और उस पर आदेश भी सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और उनकी अंतरिम जमानत की वैधता पर फैसला एक

पूरी ताकत झोंकी है। इसी कड़ी में सरकार ने अपने हर सीट पर तीन-चार मंत्रियों एक-एक की टीम बनाकर उतारा है। इस प्रकार कुल 30 मंत्रियों के कंधों पर उप चुनाव जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि 10 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन कर भाजपा लोकसभा चुनाव के घाव पर मरहम लगाना चाहती है। इसलिए मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को क्षेत्र में पूरी सिद्दत से जुटे रहने को कहा है। भाजपा का अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उससे जुड़े कार्यकर्ताओं पर करने को कहा है। दरअसल, यह उप चुनाव में सभी सीटों को जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसलिए सरकार और संगठन दोनों उप चुनाव जीतने के लिए

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर दलीलें सुनने के लिए कोर्ट ने 29 जुलाई की तारीख तय की है। इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को अभी भी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत पर बहस भी पूरी कर ली और उस पर आदेश भी सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और उनकी अंतरिम जमानत की वैधता पर फैसला एक

सप्ताह के भीतर एक साथ आने की संभावना है। इससे पहले केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि आबकारी 'घोटाला' मामले

कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर दलीलें सुनने के लिए कोर्ट ने 29 जुलाई की तारीख तय की है। इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को अभी भी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत पर बहस भी पूरी कर ली और उस पर आदेश भी सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और उनकी अंतरिम जमानत की वैधता पर फैसला एक

गुंडाराज की वापसी असंभव, 2027 चुनाव में 2017 दोहराएगी भाजपा - केशव मौर्य

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में भाजपा में दशरथ की अफवाहों के बीच, राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव पर कड़ा प्रहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूपी के उपमुख्यमंत्री मौर्य ने अखिलेश पर तंज कसते हुए उन्हें एसपी शबदादुर कह कर कहा कि बीजेपी के पास देश और प्रदेश दोनों में एक मजबूत संगठन और सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने सपा के पीडीए फॉर्मूले पर निशाना साधते हुए इसे धोखा बताया। सपा बहादुर अखिलेश यादव, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार



है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है, भाजपा 2027 विधान सभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक सोशल मीडिया

पोस्ट पर चर्चा के बीच, मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के भीतर अंदरूनी कलह से तंग आ चुकी है।

जो हमारे साथ हम उनके साथ - शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हम हिंदू और संविधान दोनों को बचाएंगे। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा को भी बंद कर देना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शुभेंदु ने भाजपा की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कहा कि हम उसका साथ देंगे, जो हमारा साथ देगा। सबका साथ सबका विकास करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगाते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास बंद हो। खास बात है कि सबका साथ, सबका विकास का नारा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। पीएम ने साल 2014 में सभी भारतीयों

को बिना किसी धर्म और जाति के शामिल करते हुए यह नारा दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मैंने राष्ट्रवादी मुसलमानों के बारे में बात की थी, लेकिन अब मैं सबका साथ, सबका विकास और नहीं कहूंगा, इसके बजाए हम कहेंगे कि जो हमारे साथ हम उनके साथ, अल्पसंख्यक मोर्चे की भी कोई जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) की सरकार है। यहां लोकसभा चुनाव 2024 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी को 42 में से 29 सीटें मिली थी। भाजपा को पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन उनको सिर्फ 12 सीटों पर जीत मिली। भाजपा पश्चिम बंगाल में संदेशवाली जैसे घटनाओं पर आक्रामक हुई थी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जौनपुर के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर कार्यालय परिसर में तीन दिवसीय धरना 18 जुलाई से होगा

जौनपुर ब्यूरो चीफ जौनपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जौनपुर के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह की अध्यक्षता

अध्यक्ष चेतनारायण सिंह सहित इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। बदलापुर और शाहगंज तहसील के शिक्षक 16 सूत्री मांगों

वेतन नहीं दिया गया तो माध्यमिक शिक्षक आजीविका के रक्षा के लिए बहुत आगे तक जाने को तैयार है। उन्होंने भी बताया कि सरकार

अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रांतीय मंत्री ने संघर्ष को ही हर मर्ज कि दवा इसलिए उसे संगठन जारी रहेगा। मण्डल अध्यक्ष सुधाकर सिंह ने वित्त विहीन को मानदेय तथा शिक्षकों के समायोजन का मुद्दा उठाया। जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने आए हुए शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा बताया कि धरने को कल तथा परसों भी जारी रहेगा। बैठक का संचालन जिला मंत्री दिनेश चक्रवर्ती ने किया। बैठक में जिला कोषाध्यक्ष प्रवीण कुमार पाण्डेय, जिला मीडिया प्रभारी विजय सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष राममताप सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, विशाल मिश्रा, नवीन सिंह, धर्मेन्द्र शर्मा, कृष्ण मोहन यादव, आलोक श्रीवास्तव, डॉ धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला, पुषेन्द्र बहादुर सिंह, पार्थ सिंह, रामजीत प्रजापति, शिव मंगल, आदि उपस्थित रहे।



में जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर कार्यालय परिसर में तीन दिवसीय धरना 18 जुलाई से प्रारंभ हो गया जो 20 जुलाई तक चलेगा। प्रदेश

के समर्थन में कार्यालय पर जमे रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को चेताया कि यदि तदर्थ शिक्षकों को सेवा बहाली तथा पूर्ण

पुरानी पेंशन बहाली के लिए सतत संघर्ष का परिणाम शीघ्र देने को बाधे। प्रदेश उपाध्यक्ष नरसिंह बहादुर सिंह ने बताया कि तदर्थ शिक्षकों का

मिशन इंद्रधनुष के तहत नहीं हो रहा बच्चों का टीकाकरण - खड़गे

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत टीकाकरण करने में कथित विफलता के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र पर निशाना साधा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, पीएम केवल घमंड की परवाह करते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने इसे मुख्य पाप करार देते हुए दावा किया कि 2023 में 16 लाख बच्चों को डिथीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (डीटीपी) और खसरे के टीके नहीं दिए गए थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सीओवीआईडी महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए लगभग आधे आवेदन पीएम

में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि नियमित टीकाकरण सेवाएं उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचें जो पहले टीकाकरण से चूक



में एक प्रमुख नियमित टीकाकरण अभियान है। 2014 में शुरू की गई योजना यह सुनिश्चित करने

गए थे या टीकाकरण कार्यक्रम से बाहर हो गए थे। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा।

प्रदेश की जनता कांग्रेस से हिसाब मांग रही - अमित शाह

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर कटाक्ष किया और इसे एक दशक का कुशासन और हरियाणा की प्रगति में बाधा करार देते हुए इसके लिए जवाबदेही की मांग की। अमित शाह ने कहा, बनिया का बेटा हूँ, पाई-पाई का हिसाब लेके चलता हूँ। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए शाह ने कहा कि आप नौकरियों में भ्रष्टाचार, जातिवाद फैलाने, उत्पीड़ितों के साथ अन्याय और भाई-भतीजावाद का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूँ हमारे दस साल और अपने दस साल का हिसाब लेकर जनता के बीच जाइए। आप हमारे से क्या हिसाब मांगेंगे। प्रदेश की जनता कांग्रेस से हिसाब

मांग रही है। अमित शाह ने कहा, आपको क्या हिसाब चाहिए? हम आपको चीजों का हिसाब देंगे और हरियाणा की जनता कांग्रेस से

सोमवार को, कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सत्तारूढ़ भाजपा की



हिसाब मांगेंगे। अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं सहित जनता से कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल के दौरान विकास परि योजनाओं के लिए आवंटित धन के ऑडिट की मांग करने का भी आग्रह किया।

आलोचना करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया था। 29 जून को पंचकुला में पार्टी की विस्तारित राज्य कार्यकारिणी बैठक में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित

त करने के बाद, अमित शाह ने एक महीने के भीतर मंगलवार को हरियाणा की अपनी दूसरी यात्रा की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में बोलते हुए, भाजपा नेता अमित शाह ने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर पिछले कांग्रेस प्रशासन की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि 2004 से 2014 तक इन सरकारों ने हरियाणा में विकास परियोजनाओं के लिए केवल ₹41,000 करोड़ आवंटित किए। इसके विपरीत, शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार, जो अपने डबल इंजन दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है, ने राज्य में विकास के लिए 2.59 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा।

संपादकीय

खुद को फिर से गढ़ने की जरूरत

परंपरा कहती है कि राजनीतिक स्थान तीन तरह से वितरित किया जाता है – वाम, दक्षिणपंथी और केंद्र। इसलिए, उनकी संरचना, संगठन के सिद्धांतों और सबसे बढ़कर विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों को तीन तरह से टैग किया जाता है। भारत में हाल ही में हुए चुनाव, खासकर केरल में, यह दर्शाते हैं कि राज्य के मतदाता, जब कष्टर–दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी, सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे और मध्यमार्गी कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे के बीच चुनाव करने का मौका देते हैं, तो वे पश्चिम बंगाल के मतदाताओं की तरह ही सामान्य पैटर्न से विचलित होते हैं। इसके विपरीत, फ्रांस के मतदाताओं ने, मरीन ले पेन के नेतृत्व में एक दूर–दराज के राष्ट्रीय रैली गठबंधन की संभावना का सामना करते हुए, अपने दूसरे विचार रखने के अधिकार का प्रयोग किया और परिणाम दक्षिणपंथी ताकतों के लिए एक आश्चर्यजनक उलटफेर, दूर–वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट के लिए एक शानदार उछाल और मध्यमार्गी–रूढ़िवादियों, विशेष रूप से राष्ट्रपति इमैनुएल मैकॉन और उनकी पुनर्जागरण पार्टी के लिए निराशा थी। दूसरे दौर के मतदान ने दूर–वामपंथियों को शीर्ष पर, मध्यमार्गियों को बीच में और दूर–दराज के दक्षिणपंथियों को नीचे रखा, जिसके परिणामस्वरूप संसद में अस्थिरता रही। केरल और पश्चिम बंगाल के साथ विरोध ाभास चौंकाने वाला है। दोनों राज्यों में, लंबे समय से वामपंथ के समर्थक रहे मतदाताओं ने पाला बदलकर भाजपा को वोट दिया है। और, कांग्रेस, जो बीच में है, ने भी लोकसभा चुनावों में बहुत हासिल की है, केरल की कुल 20 सीटों में से 18 सीटें जीती हैंय भाजपा ने सीपीआई के खिलाफ त्रिशूर से अपनी पहली जीत दर्ज की, और सीपीएम ने अलाथुर सीट बरकरार रखी। महत्वपूर्ण बदलाव उत्तरी कर्नाटक में हुआ, जहां वामपंथी गढ़ों में, मुख्यमंत्री पिनार्राई विजयन की धर्मांदाम सीट सहित रिपोर्टों से पता चला है कि भाजपा के वोट शेयर में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वामपंथी और दक्षिणपंथी सैद्धांतिक रूप से दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर, वामपंथी मतदाताओं ने दक्षिणपंथी को वोट देने के लिए प्राथमिकता दिखाई है, क्योंकि वे एक मध्यमार्गी या मध्यमार्गी पार्टी को वोट नहीं दाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में, 2014 से शुरु होकर, बड़ी संख्या में मतदाता सीपीएम से भाजपा में चले गए, और यह प्रवृत्ति नहीं बदली है। पहली बार ऐसा 2014 में हुआ था और तब से मतदाताओं ने यह तय कर लिया है कि भले ही वे सीपीएम की रैलियों में उमड़ते हैं, कोविड–19 महामारी जैसे कठिन समय में पार्टी के स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं के नेटवर्क पर निर्भर रहते हैं, लेकिन चुनावों में वे भाजपा को प्राथमिकता देते हैं। आत्मनिरीक्षण का कार्य, जिसमें गलतियों और कमियों की पहचान करना शामिल है, चुनावों के बाद राजनीतिक दलों की दिग्दर्श्या का हिस्सा है। समस्या यह है कि सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि गलतियाँ हुई थीं। सीपीएम की हाल की केंद्रीय समिति की बैठक, जिसमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए बहुत कुछ था, एक नरम स्वीकारोक्ति के साथ सामने आई कि परिणाम फिनरशासनक थे। फ्रांस में, क्रोषित दूर–दराज की राष्ट्रीय रैली ने ताजा रूप से पारदर्शी कहा कि उसने ग्वालतियों की हैं। सीपीएम, अपनी ढहती दीवारों के पीछे पीछे हटने के बजाय, यह स्वीकार करके बेहतर कर सकती थी कि न केवल अहंकार और भ्रष्टाचार ने केरल में इसके खराब प्रदर्शन में योगदान दिया था, बल्कि संगठनात्मक क्षय और अवास्तविक उम्मीदों ने इसे पश्चिम बंगाल में अपने पुनरुद्धार के लिए काम करने से रोक दिया था। यानी निदान के बिना कोई उपचार नहीं हो सकता। चुनावों में व्यक्तिगत विकल्पों और समग्र परिणामों के बीच एक अस्पष्ट संबंध है। यह अलग–अलग जगहों पर अलग–अलग परिस्थितियों में अलग–अलग तरीकों से काम करता है। हाल ही में हुए फ्रांसीसी संसदीय चुनाव में, दूसरे दौर में, दूर–दराज के वामपंथी और अन्य वामपंथी दलों, जिनमें कभी शक्तिशाली कम्युनिस्ट भी शामिल थे, ने अपनी सामूहिक शक्ति को एकत्रित किया, ट्रेड यूनियनों जैसे अपने जन संगठनों के समर्थन का लाभ उठाते हुए न्यू पॉपुलर फ्रंट के रूप में उभरे, जिसने अधिकतम सीटें जीतीं। परिणामों ने मतदाताओं के बीच एक धारणा को दर्शाया कि फ्रांस अभी तक दाईं ओर जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जर्मन नाजियों के साथ सहयोगी विद्यी शासन की सार्वजनिक स्मृति सुश्री ले पेन को जीत से वंचित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी चुनाव परिणाम को अस्थिरता की शुरुआत करने वाले विमाजित फैंसले के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसे मतदाताओं द्वारा कटु और नाजुक वामपंथी गठबंन और समान रूप से विमाजित मध्यमार्गी ताकतों को एक संकेत के रूप में भी पढ़ा जा सकता है कि वे लोकप्रिय संप्रभु को परेशान करने वाले मुद्दों को संबोधित करने का तरीका खोजें या परिणामों का सामना करें। केरल और पश्चिम बंगाल में मतदाताओं द्वारा दिए गए फैंसले के बारे में भी यही सच है, जहां भी मतदाताओं का समर्थन तीन–तरफा है। सीपीएम चौराहे पर चक्कर लगा रही है, जहां वाम, दक्षिणपंथी और केंद्र मिलते हैं। इसकी दुविधा राज्य स्तर पर है, जहां चुनाव लड़े जाते हैं और संगठन को प्रभावी होने की जरूरत है। केरल में पार्टी के भीतर समस्याएं हैं और मतदाताओं के बीच विश्वास की कमी है और हालिया लोकसभा चुनावों में भाजपा का वोट शेयर 19.18 प्रतिशत को पार कर गया, जो 2019 में 15.56 प्रतिशत और 2014 में 10.82 प्रतिशत था। इससे भी बुरी बात यह है कि 2014 के बाद से, एलडीएफ ने, भले ही लगातार दो राज्य विधानसभा चुनाव जीते हों, अब एक कर्लकति प्रतिष्ठा हासिल कर ली है।

तीन साल में योगी आदित्यनाथ कितने बदल पायेंगे हालात ?

अजय लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान उठाना पड़ा। यूपी की वजह से केंद्र में मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, जो बीजेपी यूपी में 80 सीटें जीतने का सपना पाले हुए थी, वह 33 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी का ग्राफ इतनी तेजी से गिरा की अब तो विपक्षी नेता खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो दिल्ली में मोदी को सबक सिखाने के प्रश्चात तीन साल बाद 2027 में योगी को भी ६ लूल चटाने की बात करने लगे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं और तब योगी की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। 2027 के चुनाव में जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव बड़े हुए मनोबल के साथ मैदान में उतरेंगे, वहीं बीजेपी

को 2024 के नतीजे कचोटते रहेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2024 जैसे चुनावी नतीजे 2027 विधानसभा चुनाव में नहीं देखना चाहती है। इसीलिये बीजेपी आलाकमान के



साथ–साथ सीएम योगी आ्तिथनाथ उन मुद्दों की धार कुंद करने में लग गये हैं जिसके सहारे कांग्रेस–सपा गठबंधन ने बीजेपी को आईना दिखाया था। लोकसभा चुनाव में

इंडिया गठबंधन ने संविधान, दलित ओबीसी आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई को बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत चुनावी हथियार बनाया था। अबकी से राहुल के मुंह से अडानी–अंबानी,



नोटबंदी, राफेल विमान खरीद भ्रष्टाचार, चौकीदार चोर है, जैसे तमाम जुमले सुनने को नहीं मिले थे। राहुल गांधी के साथ–साथ अखिलेश यादव भी अपनी जनसभाओं

में दो ही बातें दोहराते रहे, पहला मोदी को 400 सीटें मिली तो वह संविधान बदल देंगे, दूसरा दलितों और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर दिया जायेगा। इसके अलावा राहुल की महिलाओं को 8500 रुपये प्रति माह देने की गारंटी देना भी बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। चुनाव बाद भी जिस तरह से राहुल गांधी संविधान की किताब लिये घूम रहे हैं उसकी काट के लिये अब मोदी सरकार ने इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर कांग्रेस को घेरना शुरु कर दिया है। मोदी के मंत्री से लेकर छोटे–बड़े सभी नेता लगातार बत रहे हैं कि 1975 में किस तरह से तत्कालीन इंदिरा गांे की सरकार ने इमरजेंसी लगाकर संविधान की आत्मा को तार–तार कर दिया था। सदन में तो इमरजेंसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव तक पास

हो गया। सबसे खास बात यह रही कि मोदी सरकार जब इमरजेंसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाईं तो इसके खिलाफ कांग्रेस सदन में अकेले ही खड़ी नजर आई। राहुल के सबसे मजबूत साथी समझे जाने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इमरजेंसी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं गये। बहरहाल, आम चुनाव में इंडी गठबंधन के कुछ दमदार और असरदार साबित हुए मुद्दों की धार को मोदी सरकार कम करने में लगी है तो दूसरी ओर गठबंधन के कुछ मुद्दों की हवा निकालने के लिये योगी सरकार ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले रखी है। योगी ने इसके लिये अभी से सरकार के पेंच कसना शुरु कर दिये हैं। संगठन स्तर पर भी काम चल रहा है। यूपी वि्धानसभा चुनाव 2027 के शुरुआती तीन–चार महीनों में सम्पन्न होना

है। इस हिसाब से सरकार के पास तीन साल से भी कम का समय बचा है। यह तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी खराब छवि वाले विधायकों का प्रमुख अखिलेश यादव भी इमरजेंसी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं गये। बहरहाल, आम चुनाव में इंडी गठबंधन के कुछ दमदार और असरदार साबित हुए मुद्दों की धार को मोदी सरकार कम करने में लगी है तो दूसरी ओर गठबंधन के कुछ मुद्दों की हवा निकालने के लिये योगी सरकार ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले रखी है। योगी ने इसके लिये अभी से कांग्रेस के पेंच कसना शुरु कर दिये हैं। संगठन स्तर पर भी काम चल रहा है। यूपी वि्धानसभा चुनाव 2027 के शुरुआती तीन–चार महीनों में सम्पन्न होना

है। इस हिसाब से सरकार के पास तीन साल से भी कम का समय बचा है। यह तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी खराब छवि वाले विधायकों का प्रमुख अखिलेश यादव भी इमरजेंसी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं गये। बहरहाल, आम चुनाव में इंडी गठबंधन के कुछ दमदार और असरदार साबित हुए मुद्दों की धार को मोदी सरकार कम करने में लगी है तो दूसरी ओर गठबंधन के कुछ मुद्दों की हवा निकालने के लिये योगी सरकार ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले रखी है। योगी ने इसके लिये अभी से सरकार के पेंच कसना शुरु कर दिये हैं। संगठन स्तर पर भी काम चल रहा है। यूपी वि्धानसभा चुनाव 2027 के शुरुआती तीन–चार महीनों में सम्पन्न होना

के लिये बढ़ा मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष लगातार इसे खत्म करने की मांग कर रहा है। इस योजना के लिये बम्पर नौकरियां निकाली हैं। अभी एक लाख नौकरियां निकाले जाने की बात कही जा रही है टिकट काटने में भी आलाकमान परहेज नहीं करेगा। गौरतलब हो, हाल में सम्पन्न लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद से काफी कम सीटें मिली थीं। चुनाव आयोग ने जो आकड़े जारी किये हैं उसक अनुसार यूपी में 80 लोकसभा सीटें जिसके अंतर्गत 403 विधान सभाएं आती हैं,वहां अबकी से बीजेपी 162 विधान सभा क्षेत्रों में समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी से पिछड़ गई थी। इन 162 विधान सभा क्षेत्र के विधायकों पर भी गाज गिर सकती है। वही 2027 में विपक्ष एक बार

महाशक्तियों के बीच हथियारों की सीमा संबंधी सभी वार्ताएं खत्म

प्रशांत एनी जैकबसन की रोमांचक थ्रिलर पुस्तक श्परमाणु युद्ध रू एक परिदृश्य परमाणु युद्ध की भयावहता को स्पष्ट करती है कि कैसे दुनिया परमाणु हथियारों से नष्ट हो सकती है। इस पुस्तक को वास्तविक अर्थों में एक क्लासिक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह हमें दृढ़ता से याद दिलाती है कि हम अपने डाटाबेस से परमाणु प्रलय की काली छाया को खत्म नहीं होने देंगे। इस वर्ष की सिपरी रिपोर्ट से हमें इस भयावह परिदृश्य का एहसास होता है कि हम दुनिया भर में फैले दुश्मनों के बीच 12,121 से ज्यादा परमाणु हथियारों के साथ जी रहे हैं। अनुमान है कि अमेरिका और रूस के पास हर समय क्रमशः 1,770 और 1,710 हथियार तैनात रहते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास क्रमशः 120, 280 और 24 हथियार तैयार हैं। संप्रहीत हथियारों में जंगी 5,684 हैं और सैन्य भंडार में 9,585 हथियार हैं। इस परिदृश्य को रॉटर्स की एक रिपोर्ट और भयावह बनाती है, जिसमें बताया गया है कि रूस सैन्य अभ्यास करेगा, जिसमें जंगी परमाणु हथियारों के उपयोग का अभ्यास किया जाएगा।

शादियों की चकाचौंध और बेशुमार दौलत से कोई अछूता नहीं

मनोज हाल ही में संपन्न एक बड़े उद्योगपति के बेटे के ब्याह का खुमार में अभी उतरा नहीं है। रील्स की दुनिया में हाहाकार है। टीवी चैनलों पर सोहर जारी हैं। कोई वक्त था, जब धन के ऐसे अश्लील प्रदर्शन को समाज न केवल अनैतिक मानता था, बल्कि कई देशों में तो जेल तक हो जाया करती थी। जिनके पास अकूत दौलत थी अकरी थी, वे तब भी उसे विलासिता पर खर्च करने से पीछे नहीं रहते थे, लेकिन सामान्यतया यह सब कोटियों की बंद दीवारों के पीछे हुआ करता था। एक खास तबके के लोगों के बीच। कोशिश होती थी कि बाहर की दुनिया को इसकी ज्यादा भनक न लगे कोई खिड़की, कोई रोशनदान खुला रह गया, तो उसकी झि्रों से मीडिया

के छापामार दस्ते कुछ दृश्य चुना लाय करते थे और उसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। मगर, पिछले सालों में वक्त बदला और उसके साथ सामाजिक मूल्य भी। अब किसी को इस बात की परवाह नहीं होती कि अब भी इस देश के बड़े हिस्से में लड़की का बाप सबसे निरीह प्राणी कहा जाता है। बड़ी मिसालें हैं कि बेटे के लिए दहेज जुटाने में कई लोगों की जिंदगी भर की पूंजी खर्च हो जाती है, फिर भी ससुराल वाले संतुष्ट नहीं होते। इस बात का खतरा बना रहता है कि न जाने कब लालची की मासूम मुस्कराहटें ससुराल पक्ष की टीवी, फ्रिज और कार जैसे ठंडे लोहे की लालसाओं की भेंट चढ़ जाएं। अब इस बात को लेकर कहीं कोई फिक्र नहीं दिखती कि लकदक शादियों को फटी आंखों से देखने के

बाद दूल्हों के कस्बाई मां–बापों की हसरतें किस कदर आसामान छू रही होंगी। ब्याह में ऐसी न सही, इसके आस–पास की शान–शौकत के निष्ठुर सपने उनकी आंखों में भी कुलबुलाने लगे होंगे। मंहंगी सजावट, डिजाइनर कपड़े, नारी–भरकम गहने–जेवर और छप्पन प्रकार के व्यंजन, सब वैसा चाहिए होगा, जिसकी चकाचौंध से फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों व धर्मगुरुओं से लेकर राजनेताओं तक, सब सम्मोहित हैं। सामाजिक सरोकारों से कटे हुए, एकांगी और आत्ममुग्ध समाज इसी तरह व्यवहार करते हैं। वहां सादगी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। आजकल किसी से इस बात की अपेक्षा रखना कि वह अपने मोहल्ले के प्राथमिक शिक्षक का सम्मान करेगा, किसी कारीगर को उसकी

उजरत का पैसा चुकाते हुए विनम्र बना रहेगा या अपेक्षाकृत कमजोर आर्थिक स्थिति वाले अपने संबंधियों को भी घरेलू फोटो फ्रेम में हिस्सा देगा, बेमानी है। जब समाज के भीतर खुद मूल्यों को लेकर कोई आग्रह न हो, तो फिर जिनकी जेब में पैसा है, उनसे किसी नैतिकता और मर्यादा की अपेक्षा क्यों रखी जानी चाहिए? इस पूरे विमर्श का एक सिरा समाज में मूल्यों के ह्रास से जुड़ता है, तो दूसरा क्रोनी कैपिटलिज्म से। कहने की जरूरत नहीं कि हाल के वर्षों में एकाएक बने कई अमीरों की दौलत में पीढ़ी–दर–पीढ़ी व्यापार के विस्तार की कमाई के बजाय नए तरीकों और तंत्र के चोर दरवाजे से घुसकर जुटाई गई समृद्धि का हिस्सा है। इसलिए भी अब समाज को लेकर

नैतिक दायित्वों का कोई दबाव नहीं दिखता।

दुनिया में ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जहां उद्योगपतियों ने फाउंडेशन बनाए, चैरिटेबल ट्रस्ट खोले या फिर इसी तरह का कोई और उपक्रम करते हुए अपनी दौलत का एक में पैसा है, उनसे किसी नैतिकता और मर्यादा की अपेक्षा क्यों रखी जानी चाहिए? इस पूरे विमर्श का एक सिरा समाज में मूल्यों के ह्रास से जुड़ता है, तो दूसरा क्रोनी कैपिटलिज्म से। कहने की जरूरत नहीं कि हाल के वर्षों में एकाएक बने कई अमीरों की दौलत में पीढ़ी–दर–पीढ़ी व्यापार के विस्तार की कमाई के बजाय नए तरीकों और तंत्र के चोर दरवाजे से घुसकर जुटाई गई समृद्धि का हिस्सा है। इसलिए भी अब समाज को लेकर

भूमिका निभाई है।

मगर इन मिसालों से इतर ब्याह के नाम पर लगातार बढ़ रहे तमाशे, किशये के मेहमान, फिल्मी गानों पर दुमके और पति–पत्नी के प्रेम के प्रदर्शन के नाम पर हिंदी–अंग्रेजी फिल्मों से चुराए सस्ते संवाद बढ़ते जा रहे हैं। अधगनों मॉडलों के वार्षिक कलेंडर से लेकर मंहंगी पार्टियों तक, हवाई हजाज से लेकर यॉट की खरीद तक बैभव का प्रदर्शन करने वाले लोगों की एक शृंखला मिलेगी, जो बैंकों को दिवालियापन सौगात में देते हैं। लकदक शादियों को हसरत भरी निगाहों से देखने वाले आम लोगों को शायद इस बात का एहसास भी नहीं है कि सारे खाली खजाने आखिर में उन्हें और उनकी आने वाली पीढ़ियों को अपने ही खून–पसीने की कमाई से भरने हैं।

जौनपुर, गुरुवार, 18 जुलाई 2024

2



में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार भरना है। अमेरिका भी मानो इस होड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। अप्रैल 2023 में, अमेरिकी स्ट्रैटेजिक कमांड ने ग्लोबल थंडर नामक सैन्य

अभ्यास शुरु किया था, जिसमें देश की परमाणु कमान, नियंत्रण और संचालन प्रक्रियाओं का सफलतापूर्वक परीक्षण व सत्यापन किया गया। इसकी योजना एक साल पहले से ही बनाई जा रही थी। यह श्रणनीतिक कमान के जवानों और इकाइयों को मित्र राष्ट्रों पर गिराए गए हथियारों की तुलना में काफी अधिक ऊर्जा जारी कर सकते हैं। रूस ने इसी वर्ष जून में उत्तर कोरिया के साथ एक पारस्परिक हथियार आपूर्ति संधि शस्त्रागार को अपनी रक्षा नीति की उद्देश्य अपने शस्त्रागार को बढ़ाना और जंगी परमाणु हथियार ले जाने

बड़ा सैन्य अभ्यास शुरु किया, जिसमें 90,000 जवानों को उत्तरी अटलांटिक और यूरोप में महीनों तक चलने वाले युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार किया गया। अभ्यास मुख्य रूप से पोलैंड और नॉर्वे में हो रहे हैं, लेकिन जर्मनी, बाल्टिक राज्यों, रोमानिया, फिनलैंड, और साझेदार संगठनों के साथ प्रशिक्षण के लिए तैयार करता है, ताकि एकजुटता मजबूत की जा सके और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी अमेरिका के रणनीतिक निवारक बल

गठबंधन की क्षमता का परीक्षण करेगा। इस तरह से परमाणु टकराव की स्थिति पूरी तरह से तैयार है। इसमें चीन भी पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए उसने अपने शस्त्रागार में 90 और परमाणु हथियार जोड़ लिए हैं और उन्हें हाई अलर्ट पर रखा है। परमाणु हथियारों में इस वृद्धि के कारण स्पष्ट रूप से हैरान करने वाले हैं। दावा किया जाता है कि 11 मार्च, 2024 को अग्नि पांच पर भारत द्वारा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री–एंट्री वीकल्स (एमआईआरवी) का परीक्षण चीनी कार्रवाई को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि भारतीय अनुसंधान प्रतिष्ठान केवल अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन के उस जुनिटा समूह में शामिल होना चाहता है, जिनके पास यह क्षमता है। रणनीतिक मजबूरियों की वजह से शायद भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता! ऐसे में, हम इस धारणा से बच नहीं सकते कि हम एक अत्यंत प्रतिकूल शीतयुद्ध परमाणु परिदृश्य का सामना कर रहे हैं, जबकि ६ यान देने वाली बात है कि महाशक्तियों के बीच हथियारों की सीमा संबंधी सभी वार्ताएं खत्म हो गई हैं।

